नवभारत टाइम्स

सरकारी पैसा फंसे रहने से ग्रोथ पर पड़ता है असर: जेटली

Sep 15, 2016, 09.00 AM IST

[ईटी ब्यूरो | नई दिल्ली]

फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने कहा है कि सरकारी पैसा अनंत काल तक स्कीम्स में नहीं लगाए रखा जा सकता है क्योंकि इससे पैसे के उपयोग में दिक्कत होती है और ग्रोथ प्रभावित होती है।

पेंशनर्स के लिए एक वेब पोर्टल शुरू करने के समारोह में जेटली ने कहा, 'विभिन्न स्कीमों में सरकारी पैसा अनंत काल तक नहीं रखा जा सकता है क्योंकि इससे अक्षमता तो पैदा होती ही है, ग्रोथ में भी बाधा पड़ती है।' उन्होंने कहा कि उपयोग के अनुसार सरकारी पैसा रिलीज होना चाहिए और इसे राज्यों में यूं ही पड़े रहने नहीं दिया जा सकता है।

पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) फंड जारी करने पर नजर रखता है और इससे सुनिश्चित होता है कि राज्यों के कोषागार केंद्र के साथ एकीकृत रहें ताकि जब भी जरूरत हो, उन्हें पैसा मिल सके। PFMS को सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम भी कहा जाता है।

वित्त मंत्री ने कहा, 'PFMS मुख्य रूप से देशभर में सेंट्रल सेक्टर की स्कीमों के तहत होने वाले खर्च पर नजर रखता है। इससे हम यह देख पाने में सक्षम हुए हैं कि जिस काम के लिए पैसा जा रहा है, उसी के लिए खर्च हो रहा है या नहीं।'

जेटली ने पेंशनर्स के लिए जो वेब पोर्टल शुरू किया है, वह पेंशन के बारे में सूचना पाने और शिकायतों के तेजी से निपटारे के लिए वन-स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में काम करेगा।

इस पोर्टल के साथ 'महालेखा नियंत्रक भवन' का उद्घाटन भी किया गया, जो कंट्रोलर जनरल ऑफ एकाउंट्स के कार्यालय का नया परिसर है।

जेटली ने कहा कि पेंशनर्स के लिए वेब पोर्टल एक बेहद अहम कदम है। उन्होंने कहा, 'किसी को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। पेंशनर्स को तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि वे ज्यादातर सीनियर सिटिजन होते हैं।'

जेटली ने कहा, 'उन्हें संसाधन की जरूरत होती है। उसी पर उनका जीवन निर्भर होता है। इसलिए किसी भी तरह की देर या लालफीताशाही से उन्हें काफी परेशानी हो सकती है। इसलिए घर बैठकर या अपने मोबाइल फोन पर अगर कोई पेंशन के बारे में जानकारी ले सकेगा तो यह बहुत बड़ी सुविधा होगी।'

वेब रिस्पॉन्सिव पेंशनर्स सर्विस पोर्टल को सेंट्रल पेंशन एकाउंटिंग ऑफिस ने डिवेलप किया है। कंट्रोलर जनरल ऑफ एकाउंट्स एम जे जोसेफ ने कहा कि PFMS के रोडमैप के अनुसार केंद्र ने पहले चरण में नौ राज्यों को चुना है, जिनके साथ डेटा एक्सचेंज शुरू किया जा चुका है। दूसरे चरण में 15 और राज्यों को शामिल किया जाएगा और मार्च 2017 तक सभी राज्यों को जोड़ने का लक्ष्य है।